म के लिए कितनी धन-राशि आबंटित की गई ;

(च) क्या अधिकांश रोगियों को बहु-औषधीय चिकित्सा (मल्टी-ड्रग थिरेपी) का लाभ भी दिया जा रहा है ; और

(छ) इस रोग से ग्रस्त क्षेत्रों में क्या विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) इस समय देश में लगभग 24 लाख कुष्ठ रोगी हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपचार के अंतर्गत लाए गए और रोग-मुक्ति के बाद छोड़े गए रोगियों की राज्यवार संख्या अनुपत्र में दी गई है । [देखिए परिशिष्ट 164, अनुपत्र सं० 13]

(ग) कुष्ठ रोग से मरने वाले रोगियों के आंकड़े अलग से तैयार नहीं किए जाते हैं क्योंकि मुश्किल से ही कोई रोगी कुष्ठ रोग से मरता है ।

(घ) 1991–92 के दौरान, 23.7 प्रतिशत कुष्ठ रोगी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे ।

(ङ) 1989–90 और 1990–91 दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कोर्यक्रम के अंतर्गत किया गया वास्तविक कर्च इस प्रकार है :

वर्ष	खर्च
	(लाख रु०)
1989–90	2101.72
1990–91	2306.42

(च) जी हां ।

(छ) 201 जिलों की कुष्ठ रोग के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है । ऐसे 135 जिलों को नियमित बहु-औषध उपचार (एम० डी० टी०) के तहत पहले ही लाया गया है । शेष 66 डिलों को उपांतरित बहु-औषध उपचार के अधीन लाया गया है ।

आयुर्वेदिक महाविद्यालयों का खोला जाना

620. **श्री अजीत जोगी :**
श्री राजूभाई ए० परमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वा सरकार वर्ष 1992-93 के दौरान नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्र बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में कितने आंयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाने की संभावना हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य में नए आयुर्वेदिक कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप

621. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत उपक्रमों और संगठनों में भ्रष्टाचार की सूचनाएं मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों के विरुद्ध